व्यापार

एसयूवी की कीमत में सिलिकॉन वैली की कंपनी ला रही है उड़ने वाली कार!

कानपुर 15 जुलाई (ए)। अमरीका के टेक्नोलॉजी हब सिलिकॉन वैली की एक कंपनी ने उड़ने वाली कार को पेश किया है। इस कार को आप एसयूवी कार की कीमत में खरीद सकते हैं। इस फ्लाइंग कार का नाम है ब्लैकफ्लाई। यह कार पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक कार है, जो करीब 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से 40 किलोमीटर तक का नॉनस्टॉप सफर आसानी से कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि यह फ्लाइंग कार फ्यूचर की फ्लाइंग कार किटी हॉक और उबर की फ्लाइंग टैक्सी को जबरदस्त टक्कर देगी। इसे बनाने वाली कंपनी को उम्मीद है कि इसकी कीमत एक एसयूवी कार के आसपास ही होगी।

ट्रेनिंग के बाद कोई भी उड़ा सकता है: अमेरिका की सिलिकॉन वैली का यह स्टार्टअप प्रोजेक्ट गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज द्वारा चलाया जा रहा है। ब्लैकफ्लाई की स्टार्टअप कंपनी ओपनर के सीईओ मार्कस लेंग का दावा है कि इस कार को आसान सी बेसिक ट्रेनिंग के बाद कोई भी व्यक्ति उड़ा सकता है। बस उस व्यक्ति के पास अमरीकी कानून के मुताबिक पायलट लाइसेंस होना चाहिए। फिलहाल इस कार में एक ही सीट होगी लेकिन फिर भी यह तमाम लोगों के मन की मुराद पूरी कर देगी।

25 मिनट में फिर से चार्ज होगी कार की बैट्री: कंपनी के सीईओ के हवाले से ब्लैकफ्लाई एक बहुत ही हल्की कार है जो कि किसी भी ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक कार की तुलना में बहुत कम एनर्जी में काम कर सकती हैं। यही नहीं एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो जाने पर सिर्फ 25 मिनट में इस कार की बैटरी दोबारा से चार्ज हो सकती है। इस स्टार्टअप प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने ब्लैकफ्लाई कार बनाने का कांसेप्ट आज से 9 साल पहले सोचा था पर अब जाकर इस कार का शुरूआती प्रोटोटाइप मॉडल बन पाया है।

बहुत हल्की है ये फ्लाइंग कार, सेफ्टी के लिए कार में लगे हैं पैराशूट: ब्लैकफ्लाई फ्लाइंग कार की चौड़ाई इसकी लंबाई से अधिक है और इस कार का वजन 313 पाउंड यानि करीब 142 किलोग्राम है। यह 62 मील प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकती है। इस कार में सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर पैराशूट भी लगा हुआ है। ब्लैकफ्लाई कार प्रोजेक्ट यानी ओपनर के सीईओ मार्कस लेंग बताते हैं कि कार में मौजूद 8 छोटे इलेक्ट्रिक मोटर्स एक आसान जॉय स्टिक कंट्रोल से संचालित होते हैं। यह कार अब तक बनाए गए किसी भी फ्लाइंग कार मॉडल से काफी हल्की और सबसे बड़ी बात की बहुत ही कम कीमत की होगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि इस कार के शुरुआती मॉडल महंगे हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसे एसयूवी कार की कीमत में लोगों को उपलब्ध करा सकें।

जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन

नई दिल्ली 15 जुलाई (ए)। गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से जुड़े फैसले लेने वाली शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद इस सप्ताह विमान ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने का विचार कर सकता है, लेकिन टैक्स स्लैब इसमें बाधा खड़ा करने का काम कर रही है। मामले से जुड़े लोगों ने इसकी जानकारी दी। एक जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया था तो 5 उत्पादों- कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को होने पर नुकसान के चलते इन्हें तुरंत जीएसटी के दायरे में लाने में देरी हो रही है। हालांकि, प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राकृतिक गैस और एटीएफ को उपयुक्त माना जा रहा है। जीएसटी परिषद की बैठक 21 जुलाई को होनी है और इसमें प्राकृतिक गैस और एटीएफ को नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के दायरे में लाने का प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्री के अलावा अन्य सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि, इन दोनों उत्पादों को जीएसटी कर की दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत में रखना मुश्किल साबित हो रहा है। वर्तमान में केंद्र एटीएफ पर 14 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाता है। इसके ऊपर से राज्य 30 प्रतिशत तक सेल्स टैक्स या वैट लगाते हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में विमान ईंधन पर 5 प्रतिशत वैट है जबकि तमिलनाडु में 29 प्रतिशत, महाराष्ट्र और दिल्ली में 25 प्रतिशत और कर्नाटक में 28 प्रतिशत वैट है। टैक्स को तटस्थ रखने के लिए केंद्र और राज्यों को इस पर सहमत होना होगा। उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी दर का मतलब कम वैट वाले राज्यों में एटीएफ की कीमत में वृद्धि होगी। प्राकृतिक गैस के मामले में, उपभोक्ताओं के स्तर में कीमतों में वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार उद्योगों को बेची गयी प्राकृतिक गैस पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाती है लेकिन सीएनजी पर 14 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगता है। वहीं, दूसरी ओर राज्य 20 प्रतिशत तक वैट लगाते हैं। दिल्ली में वैट शून्य है जबकि गुजरात में वैट 12.8 प्रतिशत बिहार में 20 प्रतिशत, कर्नाटक में 14.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 13.5 प्रतिशत वैट है। सूत्रों ने कहा यदि प्राकृतिक गैस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है तो राज्यों को नुकसान होगा लेकिन अगर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है तो बिजली और उर्वरक के उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सीएनजी के लिए टैक्स निर्धारण (फिटमेंट) एक समस्या हो सकती है।

जीएसटी के कारण आम कारोबारी पारदर्शी कर व्यवस्था से जुड़ा: गोयल

जयपुर 15 जुलाई (ए)। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने देश के व्यापारी वर्ग को एक ईमानदार एवं पारदर्शी कर व्यवस्था से जुड़ने का अवसर दिया है। गोयल आज मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की मौजूदगी में जीएसटी को लेकर प्रदेशभर से आए उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले करीब एक साल से लगभग 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश के आम कारोबारी ने जिस भावना के साथ जीएसटी प्रणाली को अपनाया है वह अभूतपूर्व है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी की कामयाबी में देश के हर उस छोटे से छोटे व्यापारी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसने पहली बार कर अदायगी को कर्तव्य समझा और राष्ट्रहित में इसे स्वीकार किया। उन्होंने श्रीमती राजे द्वारा जीएसटी से जुड़ी व्यापारियों की आशंकाओं और समस्याओं को उच्च स्तर पर उठाए जाने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों की जायज समस्याओं के आधार पर समय-समय पर इसमें सुधार भी किए हैं। कर प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही एक-चौथाई से अधिक वस्तुओं की कर दरों में कमी की गई है। इस मौके उन्होंने विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के जीएसटी के संबंध में सुझाव भी लिए और कहा कि सुझावों पर विचार किया जाएगा तथा परीक्षण के बाद आवश्यक बदलाव के लिए काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा। इससे पहले राज्य के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य में जीएसटी को लेकर तहसील स्तर तक व्यापारियों से संवाद किया गया। उनकी आशंकाओं के समाधान के लिए अब तक 1200 से अधिक वर्कशॉप आयोजित की गई।

5 साल में सबसे ज्यादा हुआ भारत का व्यापारिक घाटा

नई दिल्ली 15 जुलाई (ए)। भारत का व्यापारिक घाटा जून में बीते 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे और रुपये की कमजोरी के चलते ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। भारत की ओर से विभिन्न उत्पादों का एक्सपोर्ट बीते साल की तुलना में जून में 17.57 फीसदी बढ़ा है। मई में यह आंकड़ा 14.62 अरब डॉलर का था, जो जून में बढ़कर 16.6 बिलियन डॉलर हो गया। हालांकि कच्चे तेल का इंपोर्ट भी 56.61 पर्सेंट बढ़कर 12.73 बिलियन डॉलर हो गया। दुनिया में कच्चे तेल के तीसरे सबसे बड़े आयातक देश भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। खासतौर पर अमेरिका की ओर से ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने के ऐलान के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी होने का अनुमान है। यदि ऐसा होता है तो भारत को अपने तेल इंपोर्ट के बजट में और इजाफा करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को व्यापारिक घाटा सहना पड़ेगा। ईरान के साथ 2015 में हुई न्यूक्लियर डील को खत्म करने वाला अमेरिका लगातार अपने सहयोगियों पर भी दबाव डाल रहा है कि वे तेहरान से कच्चे तेल की खरीद न करें। पिछले ही महीने रुपये के ऑल टाइम लो पर चले जाने से भी भारत के ट्रेड बैलेंस में कमी आई है। यही नहीं अगले ही साल आम चुनाव के लिए बढ़ रहे पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी रुपये की घटती कीमत और तेजी से बढ़ते व्यापारिक घाटे ने मुश्किलें पैदा करने का काम किया है।

चार्टर्ड अकाउंटैंट्स, वैल्युअर्स और मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए कड़े होने वाले हैं नियम

मुंबई 15 जुलाई (ए) मार्केट रेग्युलेटर सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने फाइनैंशल रिजल्ट्स की ऑडिटिंग एवं अन्य कार्यों के लिए लिस्टेड कंपनियों द्वारा नियुक्त ऑडिटरों और अन्य थर्ड-पार्टी इंडिविजुअल्स के लिए नियमों को कठोर करने के लिए कई संशोधनों का प्रस्ताव रखा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार करने के मकसद से बनाई गई कोटक कमिटी ने पिछले साल सिफारिश की थी कि सिक्यॉरिटीज लॉ के तहत वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए सेबी के पास ऑडिटर्स और दूसरे थर्ड पार्टी इंडिविजुअल्स या फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की स्पष्ट शक्ति होनी चाहिए।

ऑडिटिंग में खामियों के कारण वर्षों से हो रहे कई फर्जीवाड़े पकड़ में नहीं आए और पूंजी बाजार विनियामक (कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर) सेबी के पास ऑडिटिंग फर्मों पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है।

सेबी ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार देने की सिफारिश की ताकि वह किसी कानून का उल्लंघन करने या झूठा सर्टिफिकेट या रिपोर्ट देने वाले ऑडिटर या ऑडिटिंग कंपनी के खिलाफ जांच करने के बाद उचित कार्रवाई कर सके। प्रस्तावित बदलाव देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नैशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले (पीएनबी फॉड) से पर्दा उठने के बाद आया जिसकी वर्षों तक भनक तक नहीं लग पाई थी। मर्चेंट बैंकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, कस्टोडियन्स आदि का सेबी में रजिस्ट्रेशन होता है और वो सेबी के नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटैंट्स, कंपनी सेक्रटरीज, वैल्युअर्स और मॉनिटरिंग एजेंसियां किसी डायरेक्ट रेग्युलेटर के अधीन नहीं आतीं।

कानून में संशोधन से ऑडिटरों को यह सुनिश्चित करने की मजबूरी होगी कि वे जो सर्टिफिकेट या रिपोर्ट जारी करें, वे हर दृष्टिकोण से सही हों और कोई रिपोर्ट या सर्टिफिकेट जारी करते वक्त वे तमाम सावधानियां बरतें। नियमों में बदलाव के बाद किसी प्रकार का उल्लंघन पकड़ में आने पर लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमिटी या कंपनायस ऑफिसर को इसकी लिखित में रिपोर्ट देने की जिम्मेदार होगी ऑडिटर्स की होगी। जनवरी में सेबी ने प्राइस वॉटरहाउस को भारत में लिस्टेड किसी कंपनी की ऑडिटिंग करने से दो वर्षों की रोक लगा दी।

भारत के 2030 तक 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद : गर्ग

नई दिल्ली 15 जुलाई (ए)। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। साथ ही 2030 तक 10,000 अरब डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ इसके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।

गर्ग ने कहा, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी अच्छा काम हो रहा है और अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारी अर्थव्यवस्था ऊंची उड़ान के लिए तैयार है, जहां भारतीय अपना सिर गर्व से उठा सकते हैं। गर्ग ने भारतीय लागत-लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले 40 वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि दर मुश्किल से 3 से 4 प्रतिशत थी, जो आज 7-8 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि 2030 तक हम 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद कर सकते हैं। यह एक चुनौती है। साथ ही यह हमारे लिए एक अवसर भी है। गर्ग ने कहा, आठ प्रतिशत की वृद्धि दर बिल्कुल हासिल की जा सकती है अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो हम 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद कर सकते हैं। उस समय भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब भारत फ्रांस को पछाड़ कर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। विश्वबैंक के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2017 में भारत 2590 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश रहा और फ्रांस को सातवें स्थान पर खिसका दिया है। आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा, हमें 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 1,000 अरब डॉलर की डिजीटल अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद और आगे चलकर 2030 तक डिजीटल अर्थव्यवस्था के कुल अर्थव्यवस्था की आधी हो जाएगी।

टीएचएच के नेतृत्व में मजबूत होगा फोर्टिस

नई दिल्ली 15 जुलाई (ए)। फोर्टिस के प्रवर्तकों सिंह बंधुओं ने कहा कि आईएचएच हेल्थकेयर के नेतृत्व में फोर्टिस मजबूत होगा। मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह ने संयुक्त बयान में आईएचएच एवं फोर्टिस को बधाई देते हुए कहा, ''हमें विश्वास है कि संगठन नए नेतृत्व में मजबूत होगा और वह अस्पताल में आने वाले मरीजों पूरा ध्यान देते हुए विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाला इलाज देता रहेगा।'' फोर्टिस के लिए बोली लगाने में प्रतिस्पर्धी रहे मुंजाल्य-बर्मन्स ने भी उम्मीद जाहिर की कि मलेशियाई कंपनी अपनी वैश्विक क्षमताएं यहां लाएंगी और फोर्टिस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।

भारतीय महिलाओं को झटका, दुनिया से खत्म हो जाएगा सोना!

नई दिल्ली 15 जुलाई (ए)। भारतीय महिलाओं को इस खबर से झटका लग सकता है। खनन (माइनिंग) क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सोने के खनन के लिए नई जगहों की खोज नहीं होने के कारण ऐसा दिन भी आ सकता है कि दुनिया से सोना खत्म होने के आसार हैं।

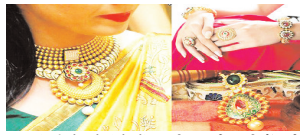

गोल्डकॉर्प के चेयरमैन इयान टेलफर का कहना है कि सोने का खनन चरम पर पहुंच चुका है। ऐसा होने का मतलब है कि दुनिया में जो भंडार था उससे सप्लाई अब गिरावट का रुख करेगी। टेलफर ने अनुमान जताया कि 2019 तक पीक गोल्ड पर पहुंच जाएंगे। सोने की खनन इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पीक गोल्ड वह स्तर है, जिसके बाद सोने की सप्लाई गिरने लगेगी। उनका कहना है कि यह स्तर बहुत जल्दी आने वाला है। इयान टेलफर का कहना है कि पिछले 40 साल में सोने का उत्पादन बढ़ता रहा है मगर अब यह बहुत जल्द गिरावट का रुख करने वाला है।

हिन्दुस्तानी शादियों की रौनक होगी फीकी: इस खबर की सच्चाई आने वाले समय में साबित हो जाएगी मगर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ तो हिन्दुस्तानी शादियों की रौनक फीकी हो जाएगी। भारतीय औरतों में जो सोने को लेकर क्रेज है, उन पर क्या असर होगा।

...तो गंवाने के बाद कमाने का रेकॉर्ड बनाने जा रहा है पीएनबी

नई दिल्ली 15 जुलाई (ए)। पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने पिछली तिमाही में गंवाने का इतिहास बना दिया था, लेकिन अगली तिमाही में वह कमाने का रेकॉर्ड बनाने जा रहा है। बैंक ने जनवरी-मार्च क्वॉर्टरली रिजल्ट में 5,367 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा होने का ऐलान किया था। लेकिन, एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पीएनबी आनेवाली जून-सितंबर तिमाही में 5,000 करोड़ रुपये की शुद्ध आमदनी घोषित करने जा रहा है।

दरअसल, रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक नीरव मोदी स्कैम के बाद पीएनबी को 3,281 करोड़ रुपये की प्रविजनिंग बढ़ाकर 11,380 करोड़ रुपये करनी पड़ी थी क्योंकि बैंक के फंसे कर्ज की रकम एक साल में ही दोगुनी से ज्यादा हो गई। दरअसल, बैंक का एनपीए मार्च 2015 के आखिर में 25,695 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 55,818 करोड़ रुपये हो गया।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब नैशनल बैंक आगामी तिमाही में दोबारा इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल, पीएनबी जून-सितंबर तिमाही में भारत के बैंकिंग इतिहास में किसी एक तिमाही में सबसे बड़ा मुनाफा दर्ज करने वाला है। यह अलग बात है कि इसके लिए बैंक अपनी कुछ ऐसेट्स बेचने जा रहा है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, पीएनबी ने जून से सितंबर महीने के बीच 5,000 करोड़ रुपये की आमदनी का लक्ष्य रखा हुआ है। बैंक यह लक्ष्य संपत्तियां बेचकर और फंसे कर्जों की वसूली करके हासिल करेगा। रिपोर्ट मुताबिक, पीएनबी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो यह देश के बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ा तिमाही लाभ होगा।

रेकॉर्ड आमदनी का बड़ा हिस्सा अपनी हाउसिंग फाइनैंस यूनिट में हिस्सेदारी बेचने से आएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएनबी और कालहिल रुप पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस में कम-से-कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस में पीएनबी बैंक का 32.79 प्रतिशत हिस्सा है जबकि कालहिल रुप ने अपनी इन्वेस्टमेंट यूनिट क्रॉलिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स के जरिए उसके पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल में 32.36 प्रतिशत हिस्सेदारी ले रखी है। पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस देश की पांचवीं सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनैंस कंपनी है। 31 मार्च तक इसके पास 62,252 करोड़ रुपये का असेट अंडर मैनेजमेंट था। मई महीने में क्रॉलिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस में 4.8 फीसदी ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए 1,024 करोड़ रुपये में बेच दी थी।

डेटा विश्लेषण में जीएसटी न चुकाने वालों का खुला राज, अब राज्य सरकार करेंगे कार्रवाई

नई दिल्ली 15 जुलाई (ए)। जीएसटीएन मंत्री समूह ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह उन कर चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्हें इन्फोसिस द्वारा तैयार डेटा विश्लेषण उपाय के जरिए चिन्हित किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने यहां जीएसटीएन मंत्री समूह की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'इन्फोसिस द्वारा बनाए गए डेटा विश्लेषण उपाय के जरिए हमने जीएसटीआर 3बी व जीएसटीआर 1 दाखिल किए जाने के दौरान बड़ी संख्या में चूककर्ताओं को पकड़ा है।' उन्होंने कहा, 'हमने दो रिपोर्ट तैयार की हैं जिन्हें राज्य सरकारों को दिया जाएगा ताकि वे चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।'

जीएसटी के कार्यान्वयन में आ रही आईटी चुनौतियों पर निगरानी रखने व उनका समाधान सुझाने के लिए गठित इस मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी हैं। बैठक में इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीण राव सहित अन्य शीर्ष कार्यकारी मौजूद थे। मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों ने चूककर्ताओं के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है तथा अन्य को भी आगाह किया है कि अगर दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंत्री समूह आईटी मोर्चे पर इन्फोसिस से पूरी तरह संतुष्ट है।